



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 117]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 15, 2009/आषाढ़ 24, 1931

No. 117]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 15, 2009/ASADHA 24, 1931

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2009

विषय : तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले तकनीकी संस्थानों, विश्वविद्यालयों सहित मानित विश्वविद्यालयों में रैगिंग पर रोकथाम और प्रतिबन्ध लगाना ।

एफ/37/3/विधिक/अभातशिप/2009.—अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 की धारा 10 के खण्ड (ख), खण्ड (छ), खण्ड (त) तथा खण्ड (च) के साथ पठित धारा 23 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :

(i) इन विनियमों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले तकनीकी संस्थानों, विश्वविद्यालयों सहित मानित विश्वविद्यालयों में रैगिंग पर रोकथाम और प्रतिबन्ध) विनियम, 2009 कहा जाएगा ।

(ii) ये अधिसूचना लागू होने की तिथि से प्रभावी होंगे ।

2. उद्देश्य :

माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष 2006 की एस.एल.पी. सं. 24295 दिनांक 16-05-2007 तथा 2009 की सिविल अपील सं. 887 दिनांक 8-5-2009 द्वारा रैगिंग की रोकथाम, प्रतिबंध तथा उन्मूलन के लिए निदेश दिए गए हैं इन्हें दृष्टिगत रखते हुए रैगिंग अर्थात् किसी विद्यार्थी अथवा विद्यार्थियों के द्वारा दूसरों को मौखिक अथवा लिखित शब्दों द्वारा प्रताड़ित करना, उसे छेड़ना, किसी नए विद्यार्थी के साथ दुर्व्यवहार करना अथवा उसे अनुशासनहीन गतिविधियों में लगाना जिससे आक्रोश, कठिनाई, मनोवैज्ञानिक क्षति हो अथवा किसी नए अथवा अन्य किसी विद्यार्थी में भय की भावना उत्पन्न हो अथवा किसी विद्यार्थी से ऐसे कार्य को करने के लिए कहना जो वह सामान्य स्थिति में न कर सके अथवा ऐसा कार्य कराना जिससे उसमें लज्जा की भावना उत्पन्न हो, पीड़ा हो, घबराहट हो अथवा मनोवैज्ञानिक दृष्टि से दुष्प्रभाव पड़े अथवा शक्ति प्रदर्शन करना अथवा वरिष्ठ होने के कारण किसी नए विद्यार्थी का शोषण करना । अतः सभी विद्यार्थियों को समुचित भौतिक और मानसिक विकास प्रदान करने के उद्देश्य से अ.भा.त.शि.प. ने ये विनियम बनाए हैं ।

## 3. परिभाषाएं :

- (क) “अधिनियम” से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का 52) अभिप्रेत है।
- (ख) “तकनीकी संस्थान” ऐसा सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त तथा निजी (स्ववित्त पोषित) संस्थान अभिप्रेत है जो तकनीकी शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के क्षेत्र में इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी, एमसीए, वास्तुकला, नगर आयोजना, प्रबंधन, भेषजी, होटल प्रबंधन एवं खानपान प्रौद्योगिकी, अनुप्रयुक्त कला एवं क्लिप तथा ऐसे अन्य कार्यक्रम तथा क्षेत्र जो समय-समय पर परिषद् द्वारा अधिसूचित किए गए हों पाठ्यक्रम/कार्यक्रम संश्लेषित करता हो।
- (ग) “विश्वविद्यालय” से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के खण्ड 2 की धारा (एफ) में परिभाषित विश्वविद्यालय अभिप्रेत है जिसमें खण्ड (3) के अन्तर्गत मानित विश्वविद्यालय संस्थान भी सम्मिलित है।
- (घ) “शैक्षिक वर्ष” से किसी संस्था में किसी विद्यार्थी का अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश तथा उस वर्ष की विशिष्ट शैक्षिक अपेक्षाओं से अभिप्रेत है।
- (ङ) “संस्थाध्यक्ष” से विश्वविद्यालय अथवा मानित विश्वविद्यालयों हेतु कुलपति अथवा किसी संस्था का निदेशक, कॉलेज का प्राचार्य, कार्यकारी अध्यक्ष अभिप्रेत है।
- (च) “फ़ेशर” से वह विद्यार्थी अभिप्रेत है जिसका प्रवेश किसी संस्था में हुआ है तथा उस संस्था में उसकी पढ़ाई का प्रथम वर्ष चल रहा है।
- (छ) जिन प्रयुक्त शब्दों तथा अभिव्यक्तियों को यहाँ स्पष्ट नहीं किया गया है किन्तु अधिनियम अथवा अधिनियम के सामान्य खण्डों, 1887 में परिभाषित है उनका वही अर्थ होगा जो अधिनियम अथवा अधिनियम के सामान्य खण्डों, 1987 में दिया गया है, जैसा भी मामला हो, तथा
- (ज) जिन अन्य शब्दों तथा अभिव्यक्तियों को यहाँ स्पष्ट नहीं किया गया है किन्तु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम अथवा 1887 (1987 का 52) में परिभाषित है उनका वही अर्थ होगा जो अधिनियम में दिया गया है।

## 4. रैगिंग में क्या सम्मिलित है :—निम्नलिखित में से कोई एक अथवा अनेक कृत्य रैगिंग के अंतर्गत आते हैं :—

- (क) किसी विद्यार्थी अथवा विद्यार्थियों द्वारा नए आने वाले विद्यार्थी का मौखिक अथवा लिखित रूप से उत्पीड़न अथवा दुर्व्यवहार या अनावश्यक सख्ती करना ;
- (ख) विद्यार्थी अथवा विद्यार्थियों द्वारा उत्पात करना अथवा अनुशासनहीनता का ऐसा वातावरण बनाना जिससे नए विद्यार्थी को कष्ट, आक्रोश, कठिनाई, शारीरिक अथवा मानसिक पीड़ा हो ;
- (ग) किसी विद्यार्थी से ऐसे कार्य को करने के लिए कहना जो वह सामान्य स्थिति में न करता हो तथा जिससे नए विद्यार्थी में शारीरिक अथवा मानसिक रूप से लज्जा, पीड़ा, अथवा भय की भावना उत्पन्न हो ;
- (घ) किसी वरिष्ठ विद्यार्थी द्वारा किया गया कोई-ऐसा कार्य जो किसी अन्य अथवा नए विद्यार्थी के शैक्षिक कार्य के निष्पादन में बाधा पहुंचाए ;
- (ङ) नए अथवा किसी अन्य विद्यार्थी का, दूसरों को दिए गए शैक्षिक कार्य को पूर्ण करने हेतु विद्यार्थी अथवा विद्यार्थियों के समूह द्वारा बाध्य कर शोषण करना ;
- (च) नए विद्यार्थी का किसी भी प्रकार से आर्थिक शोषण करना अथवा उसे खर्च का बोझ वहन करने के लिए अन्य विद्यार्थियों द्वारा बाध्य करना ;
- (छ) शारीरिक शोषण का कोई भी कृत्य जिसमें किसी भी प्रकार का जौन शोषण, समलैंगिक प्रहार, नंगा करना, अश्लील तथा काम सम्बन्धी कार्य हेतु विवश करना, अंग चालन द्वारा बुरे भावों की अभिव्यक्ति करना, किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट जिससे किसी व्यक्ति अथवा उसके स्वास्थ्य को हानि पहुंचे ;
- (ज) मौखिक रूप से किसी को गाली देना, गन्दे ई-मेल, डाक, सार्वजनिक रूप से किसी को अपमानित करना जिसमें किसी को कुमार्ग पर ले जाना, स्थानापन्न अथवा कष्ट देना या सम्पत्ती पैदा करना जिससे नए विद्यार्थी को घबराहट हो शामिल है ;
- (झ) ऐसा कोई कृत्य जिससे नए विद्यार्थियों के मन मस्तिष्क स्वास्थ्य अथवा आत्मविश्वास पर दुष्प्रभाव पड़े, वरिष्ठ साधियों द्वारा नए अथवा किसी विद्यार्थी को कुमार्ग पर ले जाना तथा उस पर किसी प्रकार की शारीरिक प्रभुता या शक्ति प्रदर्शन करना।

### 5. रैगिंग की रोकथाम के उपाय :

- (1) तकनीकी संस्थान, विश्वविद्यालय सहित मानित विश्वविद्यालय तथा/या प्रवेश प्राधिकरण/सम्बद्धता प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय/राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश/केन्द्रीय सरकार, जो भी सम्बन्धित हो, को प्रवेश के लिए विज्ञापन जारी करते समय यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित करना होगा कि रैगिंग पर सम्पूर्णतः प्रतिबन्ध है तथा यदि कोई रैगिंग करने अथवा रैगिंग के लिए उकसाने (भड़काने) का दोषी पाया गया तो उसे सजा दी जाएगी।
- (2) संबद्धता प्रदान करने वाला विश्वविद्यालय/प्रवेश प्राधिकरण/राज्य सरकार/केन्द्र सरकार, अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले संस्थानों के लिए यह अनिवार्य करे कि उनकी "विवरणिका" तथा प्रवेश से सम्बन्धित अन्य दस्तावेजों में सर्वोच्च न्यायालय के निदेश और ऐसी सूचना अनिवार्य रूप से शामिल हो। ये विनियम, अभ्यर्थियों की प्रवेश पुस्तिका/अनुदेश पुस्तिका में अनिवार्य रूप से छापे जाये।
- (3) प्रवेश/नामांकन हेतु आवेदन पत्र के साथ मुख्यतः अंग्रेजी और हिन्दी दोनों भाषाओं में तथा/अथवा किसी एक क्षेत्रीय भाषा में शपथ पत्र छपा हुआ होगा। अभ्यर्थी को इस आशय के शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा कि वह रैगिंग प्रतिबंध के लिए बनाए गए कानून तथा दण्ड के बारे में जानता है तथा यदि वह रैगिंग करने या रैगिंग को भड़काने/उकसाने का दोषी पाया गया तो उसे समुचित सजा भुगतनी होगी।
- (4) प्रवेश हेतु आवेदन पत्र मुख्यतः अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में तथा/अथवा किसी एक क्षेत्रीय भाषा में एक अन्य शपथ पत्र छपा हुआ भी होगा जिस पर अभ्यर्थी के माता-पिता/अभिभावक द्वारा इस आशय के हस्ताक्षर होंगे कि वे रैगिंग प्रतिबंध के बारे में बनाए गए कानून को जानते हैं तथा यदि उनका बच्चा रैगिंग करने या रैगिंग के लिए उकसाने का दोषी पाया गया तो वह इसके लिए निश्चित सजा का भागी होगा तथा वे इससे सहमत होंगे।
- (5) प्रवेश हेतु प्रार्थना पत्र के साथ स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र/ऐसा चरित्र प्रमाण-पत्र होगा जिसमें विद्यार्थी के व्यवहार की जानकारी दी गई हो ताकि संस्थान नकारात्मक रूप में प्रविष्ट विद्यार्थी की गहन निगरानी रख सके।
- (6) छात्रावास के लिए प्रार्थना करने वाले विद्यार्थी को छात्रावास के लिए भरे जाने वाले प्रार्थना पत्र के साथ एक अन्य शपथ पत्र जमा करना होगा कि "वह इस संदर्भ में बनाए गए कानून को जानता है/जानती है" यदि वह रैगिंग करने या इसे भड़काने/उकसाने का दोषी पाया जाता है तो उसे इसके लिए निश्चित की गई सजा भुगतनी होगी।
- (7) तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाला प्रत्येक तकनीकी संस्थान, विश्वविद्यालय सहित मानित विश्वविद्यालय प्राप्त किए गए शपथ पत्रों की डिजिटल कॉपी सहित सुरक्षित रिकार्ड रखेगा और यह डिजिटल कॉपी अभातशिप या अभातशिप द्वारा इसके लिए नामित किसी एजेन्सी को उपलब्ध करवानी होगी।
- (8) अभातशिप या अभातशिप द्वारा इस उद्देश्य के लिए नामित की गई एजेन्सी एवं संबद्धता प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय तथा सम्बन्धित राज्य के तकनीकी शिक्षा निदेशालय/संघ शासित प्रदेश, तकनीकी संस्थानों, तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले विश्वविद्यालयों सहित मानित विश्वविद्यालयों द्वारा प्रवेश के समय प्रत्येक विद्यार्थियों से प्राप्त किए गए शपथ पत्र का डिजिटल रूप में उपयुक्त डेटा बेस बनाकर रखेंगे।
- (9) नए विद्यार्थियों के प्रत्येक बैच को छोटे-छोटे वर्गों में बांटा जाएगा तथा ऐसा प्रत्येक वर्ग एक स्टॉफ सदस्य को सौंपा जाएगा जो स्वयं ग्रुप के सभी सदस्यों से चर्चा करेगा और प्रतिदिन यह देखेगा कि संस्थान में नए आए विद्यार्थियों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो तथा यदि हो तो उनकी समुचित सहायता की जाए।
- (10) नए आए विद्यार्थियों के होस्टल में प्रवेश के मामले में वर्ग प्रभारी अध्यापक का यह दायित्व होगा कि वे होस्टल वार्डन के साथ समन्वय स्थापित करे तथा होस्टल में जहां उनके वर्ग के विद्यार्थियों को रखा गया है उन कमरों में औचक निरीक्षण करते रहें। यथासंभव नए आए विद्यार्थियों को अलग होस्टल में रखा जाए और जहां इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध न हों वहां यह सुनिश्चित किया जाए कि नए विद्यार्थियों तक वरिष्ठ विद्यार्थियों की पहुंच पर वार्डन तथा सुरक्षा गार्ड और कर्मचारियों की कड़ी निगरानी रहे।
- (11) प्रत्येक संस्थान द्वारा प्रवेश के समय पेशेवर परामर्शदाता रखे जायें जो नए विद्यार्थियों को अपने आने वाले जीवन की तैयारी, विशेषतः होस्टल के जीवन से सामंजस्य स्थापित करने से सम्बन्धित परामर्श दे। शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व, तकनीकी शिक्षा संस्थान, तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालयों सहित मानित विश्वविद्यालयों के अध्यक्ष, विभिन्न अधिकारियों जैसे वार्डन, विद्यार्थी प्रतिनिधि, विद्यार्थियों के माता-पिता/अभिभावकों संकाय सदस्यों, जिला प्रशासन, पुलिस आदि से बैठक आयोजित करें तथा रैगिंग रोकने और दोषियों को पहचान कर उपयुक्त दण्ड देने पर विचार विमर्श हेतु, उन्हें सम्बोधित करें।

- (12) तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों, मानित विश्वविद्यालयों सहित विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक नए विद्यार्थी (फ्रेशर) को मुद्रित सूचना पुस्तिका दी जाएगी जिसमें यह उल्लिखित होगा कि वह विभिन्न उद्देश्यों, जिसमें वार्डन, विभागाध्यक्ष, रैगिंग-रोधी समिति, सम्बन्धित जिला और पुलिस प्राधिकरण शामिल हों, हेतु सहायता और मार्गदर्शन के लिए कब और किससे सम्पर्क कर सकता है उन सभी के पते और फोन नं. लिखे हों।
  - (13) तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों, मानित विश्वविद्यालयों सहित विश्वविद्यालयों को उक्त सूचना पुस्तिका में, प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को उनके प्रवेश तथा अभिजिन्नास की व्यवस्था के सम्बन्ध में ऐसा उल्लेख करना होगा जिससे वे विद्यार्थी के रूप में दक्ष एवं प्रभावशाली रूप में निष्पादन के लिए प्रोत्साहित हों।
  - (14) उक्त सूचना पुस्तिका में नए विद्यार्थियों को विद्यार्थी के रूप में उनके अधिकारों के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए अनुदेश दिए जाएं कि यदि उनके वरिष्ठ विद्यार्थी उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ करने को कहे तो वे ऐसा करने से मना करें, उन्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि संस्थान उनकी देखभाल करेगा और उनके खिलाफ होने वाली किसी भी ज्यादती को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
  - (15) इस सूचना पुस्तिका में संस्थान के भावी कार्यक्रमों और कार्यक्रमों एवं गतिविधियों का कैलेंडर शामिल होगा ताकि नए विद्यार्थी संस्थान के शैक्षिक पर्यावरण की जानकारी सुविधापूर्वक प्राप्त कर सकेंगे।
  - (16) समुदाय, को तथा विशेष रूप से विद्यार्थियों को रैगिंग के अमानवीय प्रभाव के सम्बन्ध में जागृत करने हेतु एवं जो रैगिंग में संलिप्त हो उनके प्रति संस्था के रवैये से अवगत कराने के लिए बड़े-बड़े पोस्टरों को (वरीयता से बहुरंगी, कानून के प्रावधानों और दण्ड इत्यादि को उजागर करते हों) होस्टल, विभागों तथा अन्य भवनों के सूचना पट्ट पर लगाया जाए। उनमें से कुछ पोस्टर स्थाई रूप के हों तथा उन्हें विशेष रूप से रैगिंग की सम्भावना वाले संवेदनशील स्थानों पर लगाया जाए।
  - (17) तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले, तकनीकी संस्थान, विश्वविद्यालय सहित मानित विश्वविद्यालय, मीडिया से अनुरोध करें कि वह रैगिंग रोकने के नियमों का प्रचार-प्रसार करें। संस्था द्वारा रैगिंग को रोकने के उपायों और इसमें लिप्त पाए जाने पर बिना भेदभाव एवं भय के उन्हें दण्डित करने के निष्पक्ष प्रचार किया जाए।
  - (18) तकनीकी संस्थान, तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय सहित मानित विश्वविद्यालय, रैगिंग के लिए संवेदनशील सभी स्थानों की पहचान कर उन्हें उचित तरीके से स्पष्ट करें और वहां आदमी तैनात रखेंगे।
  - (19) तकनीकी संस्थान, तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले विश्वविद्यालयों सहित मानित विश्वविद्यालय द्वारा परिसर में संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा कड़ी की जाए। यदि आवश्यक हो तो शैक्षिक सत्र के प्रारम्भ के महीनों में समय-समय पर पुलिस दल से इसमें सहायता ली जा सकती है।
  - (20) तकनीकी संस्थान, तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले विश्वविद्यालयों सहित मानित विश्वविद्यालय, अवकाश की अवधि में नए शैक्षिक सत्र के प्रारम्भ होने से पूर्व रैगिंग के विरुद्ध पोस्टर, सूचना पुस्तिका, सेमिनार, नुककड़ नाटकों आदि द्वारा विस्तृत प्रचार, जनमत तैयार करेंगे।
  - (21) तकनीकी संस्थानों, तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय सहित मानित विश्वविद्यालय संस्था के संकाय/विभाग/ईकाई आदि विद्यार्थियों की विशेष आवश्यकताओं का पूर्वानुमान कर निष्कारण करें तथा शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व रैगिंग निषेध सम्बन्धी अधिनियम के लक्ष्यों और उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए विधिवत् प्रबन्ध करेंगे।
  - (22) होस्टल सहित नए विद्यार्थियों के आवासीय क्षेत्रों में मोबाईल फोन और अन्य सम्पर्क उपकरणों की अनुमति दी जाए ताकि, विद्यार्थियों विशेषकर नए आए विद्यार्थियों तक, अध्यक्षों, अधिभाषकों तथा संस्थान प्राधिकरण द्वारा सहायता पहुंचाई जा सके।
6. तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों, विश्वविद्यालयों सहित मानित विश्वविद्यालयों में रैगिंग विरोधी तंत्र की निगरानी :-
- (क) रैगिंग विरोधी समिति.—प्रत्येक संस्था एक समिति बनाएगी जिसे रैगिंग विरोधी समिति (एंटी रैगिंग कमेटी) कहा जाएगा। समिति की अध्यक्षता संस्थाध्यक्ष करें तथा समिति के सदस्यों को वे ही नामांकित करेंगे। इसमें पुलिस तथा नागरिक प्रशासन के प्रतिनिधि भी हों। स्थानीय मीडिया, युवा गतिविधियों से जुड़े गैर सरकारी संगठन संकाय सदस्यों के प्रतिनिधि अभिभावकों के प्रतिनिधि, नए तथा वरिष्ठ विद्यार्थियों के प्रतिनिधि, शिक्षक कर्मचारी तथा विभिन्न वर्गों से प्रतिनिधि स्त्री पुरुष लिंग के अनुपात के आधार पर इस समिति में होंगे।

- (ख) रैगिंग विरोधी समिति का कर्तव्य होगा कि वह इन विनियम के प्रावधानों तथा रैगिंग से संबंधित कानून के प्रावधानों का अनुपालन कराए तथा रैगिंग विरोधी दल के रैगिंग रोकने संबंधी कार्यों के निष्पादन का भी अवलोकन एवं अनुवीक्षण करें।
- (ग) रैगिंग विरोधी दल.—तकनीकी संस्था, विश्वविद्यालय सहित मानित विश्वविद्यालय एक छोटे निकाय का भी गठन करे जिसे रैगिंग विरोधी दल (एंटी रैगिंग स्क्वैड) नाम से जाना जाएगा। इसे भी संस्थाध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा। यह दल नजर रखे तथा हर समय गतिशील रहते हुए तत्पर रहेगा। रैगिंग विरोधी दल/स्क्वैड में कैम्पस के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व हो। इसमें परिसर से बाहर के व्यक्ति प्रतिनिधि नहीं होंगे।
- (घ) रैगिंग विरोधी दल का यह दायित्व होगा कि वह छात्रावास तथा रैगिंग की दृष्टि से संवेदनशील अन्य स्थानों, जहां रैगिंग हो सकती है, का औचक निरीक्षण करें तथा उन्हें इन स्थानों का निरीक्षण करने की शक्तियां प्रदत्त की गई हों।
- (ङ) रैगिंग विरोधी दल का यह दायित्व होगा कि वह संस्थाध्यक्ष अथवा अन्य किसी संकाय सदस्य अथवा किसी कर्मचारी अथवा किसी विद्यार्थी अथवा किसी माता-पिता अथवा अभिभावक द्वारा सूचित की गई रैगिंग की घटना की जांच घटना स्थल पर जाकर करे तथा जांच की रिपोर्ट संस्तुति सहित रैगिंग विरोधी समिति को कार्रवाई हेतु सौंपे रैगिंग विरोधी दल इस प्रकार की जांच निष्पक्ष एवं परदर्शी विधि से करें तथा सामान्य न्याय एवं पारदर्शिता का पालन किया जाए। रैगिंग के दोषी पाए जाने वाले विद्यार्थी/विद्यार्थियों तथा गवाहों को पूरा अवसर देने तथा तथ्य एवं प्रमाण आदि देखने के बाद इसकी सूचना प्रेषित की जाए।
- (च) परामर्श प्रकोष्ठ (मैन्टोरिंग सेल)।—प्रत्येक संस्था शैक्षिक वर्ष पूर्ण होने पर इन विनियम के उद्देश्य प्राप्त करने हेतु एक परामर्श प्रकोष्ठ बनाए जिसमें नए विद्यार्थियों को परामर्श देने वाले स्वयंसेवी विद्यार्थी हों। परामर्शदाताओं की बहुस्तरीय व्यवस्था हो जो संस्था के विभिन्न बैचों की संस्था पर निर्भर होगी तथा प्रत्येक छः नए विद्यार्थियों पर एक परामर्शदाता होगा। निम्न स्तर के छः परामर्शदाताओं के ऊपर एक उच्च स्तर का परामर्शदाता होगा।
- (छ) रैगिंग पर अनुवीक्षण (मॉनीटरिंग) प्रकोष्ठ।—राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश का तकनीकी शिक्षा निदेशालय, संबद्धक विश्वविद्यालय, संबद्ध संस्थानों से समन्वय स्थापित करते हुए रैगिंग पर मॉनीटरिंग प्रकोष्ठ गठित करेगा तथा संस्थानों से रैगिंग निरोधक समितियों, दस्तों से, रैगिंग से संबंधित कार्यक्रमों की जानकारी के लिए संस्था प्रमुखों से रिपोर्ट मांगेगा तथा मॉनीटरिंग प्रकोष्ठ संस्थान से अभिविन्यास कार्यक्रमों परामर्श सत्रों आदि के संचालन संबंधी अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त करेगा और रैगिंग की घटनाओं, वार्डन तथा अन्य अधिकारियों से इस संबंध में आने वाली समस्याओं आदि के बारे में जानकारी हासिल करेगा। यह प्रकोष्ठ ऐसे संस्थानों द्वारा रैगिंग निरोधक उपायों के प्रचार प्रसार के लिए किए गए प्रयासों की समीक्षा भी करेगा तथा प्रतिवर्ष विद्यार्थियों और उनके माता-पिता/अभिभावकों से प्राप्त शपथ पत्रों की पुनः जांच का सत्यापन करेगा एवं विश्वविद्यालय अधिकरणों द्वारा सविधियों अथवा अध्यादेशों अथवा उप-नियमों में समुचित संशोधन करने के लिये की गई कार्रवाई के अनुवीक्षण की पहल करेगा ताकि संस्था के स्तर पर रैगिंग निरोधक उपायों को कार्यान्वित करने में सुविधा हो सके।
- (ज) मॉनीटरिंग सेल तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले तकनीकी संस्थानों, विश्वविद्यालयों सहित मानित विश्वविद्यालयों को इस विनियम के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु सहयोग देंगे। मॉनीटरिंग सेल संस्थाध्यक्षों, रैगिंग विरोधी समिति रैगिंग विरोधी दल से और संस्था के परामर्श प्रकोष्ठ (मैन्टोरिंग सेल) से रैगिंग की गतिविधियों की सूचना प्राप्त कर सकता है और रैगिंग विरोधी समिति आदि के निर्णय से समानता/सहमति व्यक्त करता है।
- (झ) मॉनीटरिंग सेल-संस्था द्वारा किए गए जा रहे रैगिंग विरोधी उपायों का भी मूल्यांकन करेगी। माता-पिता/अभिभावकों द्वारा प्रत्येक वर्ष में दिए गए शपथ पत्र रैगिंग के नियम तोड़ने पर दंडित किए जाने हेतु उसकी सहमति की भी जांच करेगा। दोषियों को दंडित किए जाने तथा रैगिंग विरोधी उपायों के कार्यान्वयन के लिए विधि अथवा अध्यादेश या उपविधि बनाने में भी इसकी मुख्य भूमिका होगी।

7. तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले तकनीकी संस्थान, मानित विश्वविद्यालयों सहित विश्वविद्यालयों के प्राचार्यों अथवा संस्था प्रमुख/संकाय सदस्यों/शिक्षणेतर स्टाफ के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई :—

- (1) संस्था प्रमुख अपने प्रशासनिक अधिकारियों सहित रैगिंग की रोकथाम के पर्याप्त उपाय करेंगे। इन अधिकारियों के स्तर पर बरती गई कोताही के कारण वे कानूनी कार्रवाई तथा इयूटी के प्रति लापरवाही की कार्रवाई के भागी होंगे। तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान, मानित विश्वविद्यालयों सहित विश्वविद्यालय अपने नियुक्ति प्रस्ताव पत्र में यह उप-धारा शामिल करें कि निदेशक, संकाय तथा अन्य प्रशासनिक प्रमुख अपने शैक्षिक संस्थान के प्रांगण में रैगिंग की रोकथाम के लिए सभी संभव उपाय सुनिश्चित करेंगे तथा इसका अनुपालन न करने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

2597 6709-2

- (2) प्राचार्य अथवा संस्था प्रमुख/विभागाध्यक्ष, शैक्षिक तथा शैक्षिकोत्तर स्टाफ, ठेके पर रखे गए कार्मिकों, कैटीन अथवा सफाई एवं अनुरक्षण कर्मचारियों सहित प्रत्येक कर्मचारी से वह सप्थ पत्र प्राप्त करेगा कि जैसे ही उसे पता चले वह तुरन्त रैगिंग के रिपोर्ट उसे करेगा। सेवा नियमों में यह प्रावधान रखा जाए कि ऐसे स्टाफ सदस्यों, जो रैगिंग के संबंध में रिपोर्ट करते हैं, की सेवा पुस्तिका में प्रशंसात्मक टिप्पणी की जाए और इसे सेवा रिकार्ड का एक मुख्य भाग बनाया जाए।
  - (3) ऐसे संस्था प्रमुखों/संकाय सदस्यों/शैक्षिकोत्तर स्टाफ के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के अतिरिक्त विभागीय जांच आरम्भ की जाएगी जो रैगिंग की शिकायतों के खिलाफ उदासीन अथवा संवेदनहीन रवैया अपनाएंगे और रैगिंग की रोकथाम के लिए समय पर उपयुक्त कदम न उठाते हों अथवा रैगिंग करने वाले को दंडित न करते हों।
  - (4) प्राचार्य अथवा संस्था प्रमुखों/संकाय सदस्यों/शैक्षिकोत्तर स्टाफ को यदि विद्यार्थियों की रैगिंग की रोकथाम तथा उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने में लापरवाही करते हुए पाया गया तो उन्हें तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले किसी तकनीकी संस्थान, विश्वविद्यालय सहित मान्य विश्वविद्यालय में किसी भी पद के लिए अपात्र घोषित किया जाएगा।
8. तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले तकनीकी संस्थानों, मान्य विश्वविद्यालयों सहित विश्वविद्यालयों में रैगिंग में शामिल तथा उकसाने वाले विद्यार्थियों के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई :—
- (1) रैगिंग में शामिल व्यक्ति को ऐसा दंड दिया जाए कि वह दूसरों के लिए उदाहरण हो तथा इतना कड़ा दंड दिया जाए कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।
  - (2) रैगिंग की प्रत्येक घटना के लिए बिना किसी की परवाह किए सांख्यिक अधिकारियों को स्थानीय पुलिस के समक्ष प्राथमिकी रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) दर्ज करवानी चाहिए।
  - (3) संस्था की रैगिंग विरोधी समिति, रैगिंग की प्रत्येक घटना के तथ्यों, उसके स्वरूप तथा गम्भीरता को देखते हुए दंड अथवा अन्य के संबंध में उपयुक्त निर्णय लेगी।
  - (4) क. किए गए अपराध के स्वरूप और गंभीरता को देखते हुए, जो व्यक्ति रैगिंग में संलिप्त/दोषी पाए जाएं उन्हें संस्थागत स्तर पर संभवतः कोई एक अथवा अनेक दंड दिए जा सकते हैं जो निम्नवत है :—
    - (i) प्रवेश निरस्त करना
    - (ii) कक्षा में उपस्थित होने के लिए निलंबन
    - (iii) अध्येतावृत्ति/विद्यार्थीवृत्ति तथा अन्य लाभों को रोकना/से वंचित करना
    - (iv) किसी टैस्ट/परीक्षा अथवा अन्य मूल्यांकन प्रक्रिया में उपस्थित होने से वंचित करना
    - (v) परीक्षाफल रोकना
    - (vi) किसी क्षेत्रीय राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम, टूर्नामेंट, खेल, युवा महोत्सव आदि में भाग लेने से वंचित करना
    - (vii) विद्यार्थीवास निलम्बन/निष्कासन
    - (viii) 1 से 4 सेमेस्टर तक की अवधि के लिए संस्था द्वारा रोक/निष्कासन करना
    - (ix) संस्था द्वारा निष्कासन तथा इसके परिणामस्वरूप किसी भी संस्था में प्रवेश पर रोक लगाना
    - (x) सामूहिक दंड : जब रैगिंग करने अथवा रैगिंग के लिए भड़काने वाले व्यक्तियों की पहचान न हो पाए तो संस्थान को सामूहिक रूप से दंड भुगतान होगा ताकि संघर्षित रैगिंग करने वालों पर समुदायिक रूप से दबाव बनाया जा सके।
- (4) ख. रैगिंग विरोधी समिति द्वारा दिए गए दंड विरुद्ध अपील (प्रार्थना) निम्नलिखित से की जाएगी ;
- (1) किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध संस्था अथवा संबद्ध होने की स्थिति में विश्वविद्यालय के कुलपति से
  - (2) विश्वविद्यालय का आदेश होने पर कुलपति से

- (3) संसद के अधिनियम के अनुसार गठित राष्ट्रीय महत्व की संस्था होने पर उस संस्था के अध्यक्ष अथवा कुलाधिपति से, अथवा जैसा भी मामला हो।
- (5) संस्थान के अधिकारीगण अपने प्रागण में रैगिंग होने की घटनाओं तथा उन पर की गई कार्रवाई से परिषद् को अवगत कराएंगे तथा ऐसी घटना होने के तुरन्त बाद समय-समय पर मामले की स्थिति की सूचना देते रहे।
9. तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले ऐसे तकनीकी संस्थान, मानित विश्वविद्यालयों सहित विश्वविद्यालय, जो रैगिंग रोकथाम के उपाय करने में असफल रहे हों :
1. तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले संबंधित तकनीकी संस्थानों, विश्वविद्यालयों तथा मानित विश्वविद्यालयों की भूमिका संवीक्षा हेतु स्वतंत्र होनी ताकि यह जाना जा सके कि रैगिंग में शामिल तथा/अथवा रैगिंग के लिए भड़काने के संबंध में प्रावधानों पर कार्रवाई की गई तथा रैगिंग की रोकथाम के लिए प्रभावशाली कदम उठाए गए हैं। परिषद् तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले तकनीकी संस्थानों, विश्वविद्यालयों सहित मानित विश्वविद्यालयों के निरीक्षण के लिए समिति गठित करेगी ताकि रैगिंग निरोधक उपायों की स्थिति का सत्यापन किया जा सके तथा रैगिंग की निर्दिष्ट घटनाओं की जाँच की जा सके और समुचित कार्रवाई की जा सके।
  2. तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले तकनीकी संस्थान, विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे तथा प्रतिवर्ष अभातशिप को इसकी अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे जिसमें तकनीकी संस्थान में रैगिंग की रोकथाम के लिए किए गए उपायों का विवरण दिया गया हो। अनुपालन रिपोर्ट में रैगिंग की घटनाओं का व्यापक विवरण तथा विद्यार्थियों एवं रैगिंग में शामिल तथा भड़काने वाले अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का विवरण सम्मिलित किया जाएगा।
  3. अभातशिप द्वारा जारी होने वाले सभी अनुमोदन पत्रों यथा, अनुमोदन का विस्तार, अतिरिक्त पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता में वृद्धि तथा नया तकनीकी संस्थान खोलने के लिए जारी पत्र अनुदान जारी करना, एकीकृत परिसर, द्वितीय पाली आदि के लिए जारी अनुमोदन पत्र में रैगिंग की रोकथाम की विशिष्ट धारा समाहित होगी।
  4. कोई भी संस्था जो रैगिंग रोकने के लिए इन विनियमों के अनुसार कार्रवाई नहीं करेगी अथवा दोषियों को दण्डित नहीं करती, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् उसके विरुद्ध निम्नलिखित में से कोई एक अथवा अनेक कार्रवाई करेगी :—
    - (i) अभातशिप अधिनियम 10(ट) के अंतर्गत प्रवेश न देना/अनुमोदन की वापसी।
    - (ii) दिया जा रहा कोई अनुदान वापस लेना।
    - (iii) अभातशिप द्वारा दी जाने वाली सामान्य सहायता अथवा किसी विशेष कार्यक्रम में सहायता हेतु विचार करने के लिए संस्था को आयोग्य घोषित करना।
    - (iv) सामान्य जनता तथा संभावी अभ्यर्थियों को इस सूचना से अवगत करवाना, मीडिया, अभातशिप की वेबसाइट आदि द्वारा यह घोषित करना कि संस्था का न्यूनतम शैक्षिक स्तर भी नहीं है।
    - (v) इसी प्रकार की अन्य कार्रवाई करना तथा इसी प्रकार से संस्था को तब तक दंडित करना जब तक कि वे रैगिंग रोकने के लक्ष्य को प्राप्त न कर ले अभातशिप द्वारा किसी संस्थान के विरुद्ध इस अधिनियम के विनियमों के प्रावधानों के अनुसार की गई कार्रवाई में सभी समितियों सहयोग देंगी।
  5. जहाँ तक तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले विश्वविद्यालयों तथा मानित विश्वविद्यालयों का संबंध है उनके विरुद्ध अनुदान रोकने, अनुमोदन/मान्यता की वापसी के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.), मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एम.एच.आर.डी.) भारत सरकार तथा संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश सरकार को कार्रवाई के लिए प्रस्तावित किया जाएगा। यू.जी.सी., एम.एच.आर.डी. भारत सरकार तथा राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश सरकार परिषद् की संस्तुतियों पर तुरंत कार्रवाई करेगी।

#### 10. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के कर्तव्य और दायित्व :

- (क) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अथवा केन्द्र सरकार अथवा इस उद्देश्य के लिए बनाई गई एजेंसी निधि निर्धारित तथा संचालित करेगी तथा एक टोल फ्री रैगिंग विरोधी हैल्पलाइन बनाएगी जो 24 घंटे खुली रहेगी जिसका विद्यार्थी, रैगिंग से संबंधित घटनाओं के निवारण हेतु प्रयोग कर सकते हैं।

- (ख) रैगिंग विरोधी हेल्पलाइन पर प्राप्त किया गया संदेश तुरन्त संस्थाध्यक्ष, छात्रवास के वार्डन, सम्बद्ध विश्वविद्यालय के नोडल अधिकारी को प्रसारित किया जाएगा। सम्बद्ध जिला अधिकारियों यदि आवश्यकता हो तो जिला अधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक को तुरन्त सूचना दी जाएगी तथा ऐसी जानकारी वेबसाइट पर डाल दी जाएगी ताकि मीडिया तथा सामान्य जनता तक जानकारी पहुंच सके।
- (ग) संस्थाध्यक्ष को एंटी-रैगिंग हेल्पलाइन पर मिली सूचना पर त्वरित कार्रवाई इन विनियम के उप-खण्ड (बी) के अनुसार करनी होगी।
- (घ) किसी भी व्यक्ति को रैगिंग विरोधी हेल्पलाइन पर संदेश देने हेतु संस्था, मेन्सल और फोन के बे-रोक-टोक प्रयोग की सभी स्थानों पर अनुमति देगी। रैगिंग विरोधी हेल्पलाइन तथा अन्य महत्वपूर्ण अधिकारियों, संस्थाध्यक्षों संकाय के सदस्यों, रैगिंग विरोधी समिति के सदस्यों तथा रैगिंग विरोधी दल, जिले के अधिकारियों, हॉस्टल के वार्डनों तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारियों के फोन नम्बर तथा पते विद्यार्थियों तथा जनसम्पर्क को उपलब्ध कराए जाएँ ताकि आपातस्थिति में उसका प्रयोग सुनिश्चित हो सके।
- (ङ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् केन्द्र सरकार और इस उद्देश्य के लिए बनाई गई एजेन्सी विद्यार्थियों तथा उसके माता-पिता/अभिभावकों द्वारा दिए गए शपथ पत्रों के आधार पर डेटा बेस आंकड़ा रखेगा। यह आंकड़े रैगिंग की शिकायतों तथा उस पर की गई कार्रवाई के रिकार्ड के रूप में रखे जाएंगे।
- (च) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् केन्द्र सरकार और इस उद्देश्य के लिए बनाई गई एजेन्सी इस आंकड़े को केन्द्र सरकार द्वारा नामित एवं गैर सरकारी संगठनों को उपलब्ध कराएगा। इससे आम जनता में विश्वास बढ़ेगा, इन विनियमों के अनुपालन न करने की सूचना अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् केन्द्र सरकार द्वारा अधिकृत समितियों को उपलब्ध करवाई जाती है।
11. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् निम्न के अनुसार निम्नलिखित कदम उठाएगा :
- (क) संस्था हेतु यह अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अनिवार्य करेगा कि वह अपनी विवरणिका में केन्द्र सरकार के निर्देश अथवा राज्य स्तरीय मॉनीटरिंग समिति के रैगिंग निषेध सम्बन्धी निर्देश और उसके परिणाम समाहित करें। यदि वे ऐसा नहीं करते तो यह माना जाएगा कि वे शिक्षा का स्तर गिरा रहे हैं तथा इसके लिए उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी।
- (ख) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् यह स्थापन करेगा कि इन विनियमों के अनुसार विद्यार्थियों तथा उनके माता-पिता/अभिभावक से शपथ पत्र संस्था द्वारा प्राप्त करने का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।
- (ग) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा यह निर्दिष्ट शर्त भी लगाई जाएगी कि उसके द्वारा संस्था को दी जा रही किसी प्रकार की विशेष अथवा सामान्य आर्थिक सहायता अथवा अनुदान के उपयोगिता प्रमाण पत्र में एक शर्त यह होगी कि संस्था द्वारा रैगिंग निषेध संबंधी विनियम एवं उपायों का अनुपालन किया जा रहा है।
- (घ) रैगिंग की किसी भी घटना का संस्था के प्रत्यायन अथवा राष्ट्रीय प्रत्यायन मंडल अथवा किसी अन्य सक्षम एजेंसी द्वारा दिए जाने वाले स्तरमानों अथवा ग्रेडिंग पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है।
- (ङ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् रैगिंग रोकने के लिए एक अंतः परिषद् समिति बनाएगा जिसमें की विभिन्न परिषदों के प्रतिनिधि होंगे। गैर-सरकारी एजेंसी/अभ्युक्ति द्वारा रखे जा रहे आंकड़े को देखने के लिए उत्तरदायी होगी जिसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/केन्द्र सरकार द्वारा अनुमति किया जाएगा तथा इस प्रकार के निकाय उच्चतर शिक्षा में रैगिंग विरोधी उपायों को देखने तथा सहयोग देने हेतु सक्षम होंगे तथा समय-समय पर संस्तुतियाँ देंगे और प्रत्येक छः महीने में इसकी कम से कम एक बैठक होगी।
- (च) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् एक रैगिंग विरोधी प्रकोष्ठ अभ्युक्ति में बनाएगा जो रैगिंग से संबंधित सूचनाएं एकत्र करने तथा उस पर दृष्टि रखने में सहायता करेगा तथा राज्य स्तरीय मॉनीटरिंग प्रकोष्ठ तथा विश्वविद्यालय स्तरीय समितियाँ रैगिंग निरोधक उपायों के प्रभावकारी कार्यान्वयन के लिए उपाय सुझाएंगी। यह सैल गैर-सरकारी एजेंसी जो रैगिंग रोकने से संबंधित होंगे, अभ्युक्ति द्वारा बनाए गए आंकड़ों की देखरेख में सहायता देगा।

[सं. विज्ञापन/III/4/असल/162/09]

डॉ. के. नारायण राव, सदस्य सचिव



**ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION****NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st July, 2009

**Sub : Prevention and prohibition of Ragging in technical Institutions, Universities including Deemed to be Universities imparting technical education.**

**F.No.37-3/Legal/AICTE/2009** - In exercise of the powers conferred under Section 23 read with Section 10 (b), (g), (p) and (q) of AICTE Act, 1987, the All India Council for Technical Education, hereby makes the following Regulations :—

**1. Short title and commencement :—**

- (i) These Regulations may be called the All India Council for Technical Education (Prevention and Prohibition of Ragging in Technical Institutions, Universities including Deemed to be Universities imparting technical education) Regulations, 2009.
- (ii) They shall come into force on the date of the notification.

**2. Objectives :—**

In view of the directions of the Hon'ble Supreme Court in SLP No. 24295 of 2006 dated 16-05-2007 and in Civil Appeal number 887 of 2009, dated 08-05-2009 to prohibit, prevent and eliminate the scourge of ragging including any conduct by any student or students whether by words spoken or written or by an act which has the effect of teasing, treating or handling with rudeness a fresher or any other student, or indulging in rowdy or undisciplined activities by any student or students which causes or is likely to cause annoyance, hardship or psychological harm or to raise fear or apprehension thereof in any fresher or any other student or asking any student to do any act which such student will not in the ordinary course do and which has the effect of causing or generating a sense of shame, or torment or embarrassment so as to adversely affect the physique or psyche of such fresher or any other student, with or without an intent to derive a sadistic pleasure or showing off power, authority or superiority by a student over any fresher or any other student, in all higher education institutions in the country, and thereby, to provide for the healthy development, physically and psychologically, of all students, the All India Council for Technical Education, (AICTE) brings forth these Regulations.

**3. Definitions :—**

- (a) "Act" means the All India Council for Technical Education Act, 1987 (52 of 1987);
- (b) "Technical Institution" means an institution of Government, Government Aided and Private (self financing) conducting the courses/

programmes in the field of technical education, training and research in Engineering, Technology including MCA, Architecture, Town Planning, Management, Pharmacy, Hotel Management & Catering Technology, Applied Arts & Crafts and such other programmes and areas as notified by the Council from time to time;

- (c) "University" means a University defined under clause (f) of section 2 of the University Grants Commission Act, 1956 and includes and institution deemed to be a University under section 3 of that Act.
- (d) "Academic year" means the period from the commencement of admission of students in any course of study in the institution up to the completion of academic requirements for that particular year.
- (e) "Head of the institution" means the Vice-Chancellor in case of a university or a deemed to be university, the Principal or the Director or such other designation as the executive head of the institution or the college is referred.
- (f) "Fresher" means a student who has been admitted to an institution and who is undergoing his/her first year of study in such institution.
- (g) Words and expressions used and not defined herein but defined in the Act or in the General Clauses Act, 1887, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act or in the General Clauses Act, 1887, as the case may be. And
- (h) All other words and expressions used herein and not defined but defined in the All India Council for Technical Education Act, 1987 (52 of 1987), shall have the meanings respectively assigned to them in the said Act;

**4. What constitutes Ragging :—**Ragging constitutes one or more of any of the following acts :

- a. any conduct by any student or students whether by words spoken or written or by an act which has the effect of teasing, treating or handling with rudeness a fresher or any other student;
- b. indulging in rowdy or undisciplined activities by any student or students which causes or is likely to cause annoyance, hardship, physical or psychological harm or to raise fear or apprehension thereof in any fresher or any other student;
- c. asking any student to do any act which such student will not in the ordinary course do and

2597 4709-3

- which has the effect of causing or generating a sense of shame, or torment or embarrassment so as to adversely affect the physique or psyche of such fresher or any other student;
- d. any act by a senior student that prevents, disrupts or disturbs the regular academic activity of any other student or a fresher;
  - e. exploiting the services of a fresher or any other student for completing the academic tasks assigned to an individual or a group of students.
  - f. any act of financial extortion or forceful expenditure burden put on a fresher or any other student by students;
  - g. any act of physical abuse including all variants of it: sexual abuse, homosexual assaults, stripping, forcing obscene and lewd acts, gestures, causing bodily harm or any other danger to health or person;
  - h. any act or abuse by spoken words, emails, posts, public insults which would also include deriving perverted pleasure, vicarious or sadistic thrill from actively or passively participating in the discomfiture to fresher or any other student;
  - i. any act that affects the mental health and self-confidence of a fresher or any other student with or without an intent to derive a sadistic pleasure or showing off power, authority or superiority by a student over any fresher or any other student.

#### 5. Measures for prevention of ragging :—

It shall be mandatory for every technical Institution, University, deemed to be University imparting technical education to take following measures for prevention of ragging at such institutions.

1. The advertisement issued for admission by a technical institution, University including Deemed to be University concerned and/or the admission authority/affiliating University/State Govt./UT/Central Govt. as the case may be, shall clearly mention that ragging is totally banned and anyone found guilty of ragging and/or abetting ragging is liable to be punished.

2. The 'Prospectus' and other admission related documents shall contain directions of the Supreme Court Affiliating University/admission Authority/State Govt./Central Govt. shall make it mandatory for the institutions under their jurisdiction to compulsorily incorporate such information in their 'Prospectus'. These Regulations shall be printed in the brochure of admission/instruction booklet for candidates.

3. The application form for admission/enrolment shall have a printed affidavit, preferably both in English and

Hindi and/or in one of the regional languages. The affidavit should be filled up and signed by the candidate to the effect that he/she is aware of the law regarding prohibition of ragging as well as the punishments, and that he/she, if found guilty of the offence of ragging and/or abetting ragging, is liable to be punished appropriately.

4. The application form shall also contain a printed affidavit, preferably both in English and Hindi and/or in one of the regional languages and the affidavit should be signed by the parent/guardian of the applicant to the effect that he/she is also aware of the law in this regard and agrees to abide by the punishment meted out to his/her ward in case the latter is found guilty of ragging and/or abetting ragging.

5. The application for admission shall be accompanied by a document along with the School Leaving Certificate/Character Certificate which shall include a report on the behavioral pattern of the applicant, so that the institution can thereafter keep intense watch upon the student who has a negative entry in this regard.

6. A student seeking admission to the hostel shall have to submit another affidavit along with his/her application for hostel accommodation that he/she is also aware of the law in this regard and agrees to abide by the punishments meted out if he/she is found guilty of ragging and/or abetting ragging.

7. Every technical institution, University including Deemed to be University imparting technical education shall maintain a proper record of the affidavits obtained to ensure its safe up keep thereof, including digital copies of the affidavits and such digital copy should be made available to the AICTE or to an Agency identified/nominated by AICTE.

8. The AICTE or an Agency identified/nominated for the purpose and affiliating Universities and Directorate of Technical Education of the concerned State Govt./UT shall maintain an appropriate data base of the affidavits in the digital form obtained from every student at the time of admission to the technical institutions, Universities including Deemed to be Universities imparting technical education.

9. Each batch of freshers should be divided into small groups and each such group shall be assigned to a member of staff. Such staff member should interact individually with each member of the group on daily basis to ascertain the problems/difficulties, if any faced by the freshers in the Institution and extend necessary help.

10. In case of freshers admitted to a Hostel it shall be the responsibility of the teacher incharge of the group to co-ordinate with the warden of the Hostel and to make surprise visits to the rooms in the hostel where the members of the group are lodged. Freshers should be lodged in a separate hostel block wherever possible and where such

facilities are not available, the college/institution shall ensure that seniors' access to freshers' accommodation is strictly monitored by wardens, Security Guards and Staff.

11. Every institution should engage or seek the assistance of professional counsellors at the time of admissions to counsel 'freshers' in order to prepare them for the life ahead, particularly for adjusting to the life in hostels. At the commencement of the academic session the Head of the Technical Institution, University including Deemed to be University imparting technical education shall convene and address a meeting of various functionaries/agencies, like Wardens, representatives of students, parents/guardians, faculty, district administration including police, to discuss the measures to be taken to prevent ragging and steps to be taken to identify the offenders and punish them suitably.

12. Every fresher admitted to the Technical Institution, University including Deemed to be University imparting technical education shall be given a printed information booklet detailing when and whom he/she has to turn to for help and guidance for various purposes (including Wardens, Head of the institution, members of the anti-ragging committee, relevant district and police authorities), addresses and telephone numbers of such persons/authorities, etc.

13. The technical institutions, University including Deemed to be University imparting technical education through the information booklet mentioned above shall explain to the new entrants the arrangements for their induction and orientation which promote efficient and effective means of integrating them fully as students.

14. The information booklet mentioned above shall also tell the freshers about their rights as *bona fide* students and clearly instructing them that they should desist from doing anything against their will even if ordered by the seniors, and that they have nothing to fear as the institution cares for them and shall not tolerate any atrocities against them.

15. The information booklet mentioned above shall contain a calendar of events and activities laid down by the institution to facilitate and complement familiarization of juniors with the academic environment of the institution.

16. To make the community at large and the students in particular aware of the dehumanizing effect of ragging, and the approach of the institution towards those indulging in ragging, big posters (preferably with different colours for the provisions of law, punishments, etc.) shall be prominently displayed on all Notice Boards of all departments, hostels and other buildings as well as at vulnerable places. Some of such posters shall be of permanent nature in certain vulnerable places.

17. The Technical Institution, University including Deemed to be University imparting technical education

shall request the media to give adequate publicity to the law prohibiting ragging and the negative aspects of ragging and the institutions' resolve to ban ragging and punish those found guilty without fear or favour.

18. The Technical Institution, University including Deemed to be University imparting technical education shall identify, properly illuminate and mark all vulnerable locations.

19. The Technical Institution, University including Deemed to be University imparting technical education shall tighten security in its premises, especially at the vulnerable places. If necessary, intense policing shall be resorted to at such points at odd hours during the early months of the academic session.

20. The Technical Institution, University including Deemed to be University imparting technical education shall utilize the vacation period before the start of the new academic year to launch wide publicity campaign against ragging through posters, information booklets, seminars, street plays, etc.

21. The faculties/departments/units of the Technical Institution, University including Deemed to be University imparting Technical education shall have induction arrangements (including those which anticipate, identify and plan to meet any special needs of any specific section of students) in place well in advance of the beginning of the academic year with a clear sense of the main aims and objectives of the induction process.

22. Mobile Phones and other communication devices may be permitted in residential areas including hostels to provide access to the students particularly freshers, to reach out for help from teachers, parents and Institution authorities.

**6. Monitoring mechanism in technical institution, University including Deemed to be University imparting technical education :—**

(a) **Anti-ragging Committee :** Every Institution University including Deemed to be University imparting technical education shall constitute a Committee to be known as the Anti-ragging Committee to be nominated and headed by the Head of the Institution, and consisting of representatives of civil and police administration, local media, Non Government Organizations involved in youth activities, representatives of faculty members, representatives of parents, representatives of students belonging to the freshers' category as well as senior students, non-teaching staff; and shall have a diverse mix of membership in terms of level as well as gender.

(b) It shall be the duty of the Anti-Ragging Committee to ensure compliance with the

provisions of these Regulations as well as the provisions of any law for the time being in force concerning ragging; and also to monitor and oversee the performance of the Anti-Ragging Squad in prevention of ragging in the institution.

- (c) **Anti-Ragging Squad.**—Every Institution University including Deemed to be University imparting technical education shall also constitute a smaller body to be known as the Anti-Ragging Squad to be nominated by the Head of the Institution with such representation as may be considered necessary for maintaining vigil, oversight and patrolling functions and shall remain mobile, alert and active at all times. Provided that the Anti-Ragging Squad shall have representation of various members of the campus community and shall have no outside representation.
- (d) It shall be the duty of the Anti-Ragging Squad to be called upon to make surprise raids on hostels, and other places vulnerable to incidents and having the potential for ragging and shall be empowered to inspect such places.
- (e) It shall also be the duty of the Anti-Ragging Squad to conduct an on-the-spot enquiry into any incidents of ragging referred to it by the Head of the institution or any member of the faculty or any member of the staff or any student or any parent or guardian or any employee of a service provider or by any other person, as the case may be; and the enquiry report along with recommendations shall be submitted to the Anti-Ragging Committee for action. Provided that the Anti-Ragging Squad shall conduct such enquiry observing a fair and transparent procedure and the principles of natural justice and after giving adequate opportunity to the student or students accused of ragging and other witnesses to place before it the facts, documents and views concerning the incidents of ragging, and considerations such other relevant information as may be required.
- (f) **Mentoring Cell.**—Every institution shall, at the end of each academic year, in order to promote the objectives of these Regulations, constitute a Mentoring Cell consisting of students volunteering to be Mentors for freshers, in the succeeding academic year; and there shall be as many levels or tiers of Mentors as the number of batches in the institution, at the rate of one Mentor for six freshers and one Mentor of a higher level for six Mentors of the lower level.

- (g) **Monitoring Cell on Ragging.**—The State Govt./UT and the affiliating University shall set up a Monitoring Cell on Ragging to coordinate with the institutions to monitor the activities of the Anti-Ragging Committees, Squads, and Mentoring Cells, regarding compliance with the instructions on conducting orientation programmes, counselling sessions, etc., and regarding the incidents of ragging, the problem faced by wardens and other officials, etc. This Cell shall also review the efforts made by such institutions to publicize anti-ragging measures, cross-verify the receipt of affidavits from candidates/students and their parents/guardians every year, and shall be the prime mover for initiating action by the University authorities to suitably amend the Statutes or Ordinances or Bye-laws to facilitate the implementation of anti-ragging measures at the level of the institution.
- (h) The Monitoring Cell shall coordinate with the institutions, universities including deemed to be universities imparting technical education to achieve the objectives of these Regulations; and the Monitoring Cell shall call for reports from the Heads of institutions in regard to the activities of the Anti-Ragging Committees, Anti-Ragging Squads, and the Mentoring Cells at the institutions, and it shall also keep itself abreast of the decisions of the Anti-Ragging Committees etc.
- (i) The Monitoring Cell shall also review the efforts made by institutions to publicize anti-ragging measures, soliciting of affidavits from parents/guardians and from students, each academic year, to abstain from ragging activities or willingness to be penalized for violation; and shall function as the prime mover for initiating action for amending the Statutes or Ordinances or Bye-laws to facilitate the implementation of anti-raigging measures at the level of the institution.

**7. Action to be taken against the Principal or the Head of the Institution/Faculty Members/Non-Teaching staff of Technical Institution, Universities including Deemed to be Universities imparting Technical Education.**

- 1. The Head of the Institution along with other administrative authorities should take adequate measures for prevention of ragging. Any lapse on the part of these authorities shall make them liable for criminal action for negligence of duty. The technical Institution, University including Deemed to be University imparting technical education should

incorporate a clause in their letter of appointment that the Director, Faculty and other administrative Heads should ensure all possible steps for prevention of ragging in the premises of the educational institutions, and that they are liable for action, in case of non-compliance.

2. The Principal or Head of the Institution/Department shall obtain an affidavit from every employee of the Institution including teaching/non-teaching staff, contract labor employed in the premises either for running canteen or as watch and ward staff or for cleaning or maintenance of the building, lawns etc. that he/she would report promptly any case of ragging which comes to his/her notice. A provision shall be made in the service rules for issuing certificates of appreciation to such members of the staff who report ragging which will form part of their service records.
3. Departmental enquiries shall be initiated, in addition to penal consequences against such Heads of the Institution/Faculty Members/Non-teaching staff who display an apathetic or insensitive attitude towards complaints of ragging and would not take timely steps in the prevention of ragging and punishing those who rag.
4. The Principal or the Head of the Institution/Faculty Members/Non-teaching staff, if found negligent in taking necessary measures for ensuring safety of students and preventing; the ragging would be declared unfit for holding any post in any technical institution, University including Deemed to be University imparting technical education.

**8. Actions to be taken against students for indulging and abetting ragging in technical institutions Universities including Deemed to be University imparting technical education :—**

1. The punishment to be meted out to the persons indulged in ragging has to be exemplary and justifiably harsh to act as a deterrent against recurrence of such incidents.
2. Every single incident of ragging a First Information Report (FIR) must be filed without exception by the institutional authorities with the local police authorities.
3. The Anti-ragging Committee of the institution shall take an appropriate decision, with regard to punishment or otherwise, depending on the facts of each incident of ragging and nature and gravity of the incident of ragging.

4. (a) Depending upon the nature and gravity of the offence as established the possible punishments for those found guilty of ragging at the institution level shall be anyone or any combination of the following :

- (i) Cancellation of admission;
- (ii) Suspension from attending classes;
- (iii) Withholding/withdrawing scholarship/fellowship and other benefits;
- (iv) Debarring from appearing in any test/examination or other evaluation process;
- (v) Withholding results;
- (vi) Debarring from representing the institution in any regional, national or international meet, tournament, youth festival, etc.;
- (vii) Suspension/expulsion from the hostel;
- (viii) Rustication from the institution for period ranging from 1 to 4 semesters;
- (ix) Expulsion from the institution and consequent debarring from admission to any other institution;
- (x) Collective punishment: when the persons committing or abetting the crime of ragging are not identified, the institution shall resort to collective punishment as a deterrent to ensure community pressure on the potential raggars.
- (b) An appeal against the order of punishment by the Anti-ragging Committee shall lie,
  - (i) In case of an order of an institution, affiliated to or constituent part, of the University, to the Vice-Chancellor of the University;
  - (ii) In case of an order of a University, to its Chancellor;
  - (iii) In case of an institution of national importance created by an Act of Parliament, to the Chairman or Chancellor of the Institution, as the case may be.
5. The institutional authorities shall intimate the incidents of ragging occurred in their premises along with actions taken to the Council from time to time.

**9. Action to be taken against the technical Institution, University including Deemed to be University imparting technical education which fail to take measures for prevention of ragging :—**

1. Role of the concerned technical institutions, Universities including Deemed to be Universities imparting technical education shall be open to scrutiny for the purpose of

2597 9709-4

- finding out whether they have taken effective steps for preventing ragging and action taken against provision indulged and/or abetting ragging. The Council shall constitute Committees to inspect technical institutions, Universities including Deemed to be Universities imparting technical education to verify the status of anti-ragging measures and to investigate specific instances of ragging and take appropriate action.
2. The technical Institution, University including Deemed to be University imparting technical education should submit an affidavit along with its compliance report submitted to AICTE annually with details of measures taken for prevention of ragging in technical institutions. The Compliance Report should also contain the details of the instances of ragging and action taken against students, and others for indulging and abetting ragging.
  3. All Letters of Approval issued by AICTE such as extension of approval letters, letters issued for additional courses/increase in intake and letters issued for new technical institutions, release of grants, letters of approval issued to integrated campus, second shift etc. shall contain a specific clause of prevention of ragging.
  4. The AICTE shall, in respect of any institution that fails to take adequate steps to prevent ragging or fails to act in accordance with these Regulations or fails to punish perpetrators or incidents of ragging suitably, take one of more of the following measures, namely:—
    - (i) No admission/withdrawal of approval granted under Section 10(k) of AICTE Act.
    - (ii) Withholding any grant allocated.
    - (iii) Declaring the institution ineligible for consideration for any assistance under any of the general or special assistance programmes of the AICTE.
    - (iv) Informing the general public, including potential candidates for admission, through a notice displayed prominently in the newspapers or other suitable media and posted on the website of the AICTE, declaring that the institution does not possess the minimum academic standards.
    - (v) Taking such other action within its powers as it may deem fit and impose such other penalties as may be provided in the Act for such duration of time as the institution complies with, the provisions of these Regulations.
  5. As regards the Universities including Deemed to be Universities imparting technical education the actions proposed to be taken such as stopping release of grants, withdrawal of approval/recognition will be sent to University Grants Commission (UGC), Ministry of Human Resource Development (MHRD), Govt. of India and the concerned State Govt./UT. The UGC, MHRD Govt. of India, and the State Govt./UT concerned shall initiate immediate action on the recommendations of the Council.
- 10. Duties and Responsibilities of the All India Council for Technical Education :—**
- (a) All India Council for Technical Education, or the Central Government or the agency authorized for the purpose shall establish, fund and operate, a toll free Anti-ragging Helpline, operational round the clock, which could be accessed by students in distress owing to ragging related incidents.
  - (b) Any distress message received at the Anti-ragging Helpline shall be simultaneously relayed to the Head of the Institution, the Warden of the Hostels, the Nodal Officer of the affiliating University, if the incident reported has taken place in an institution affiliated to a University, the concerned District authorities and if so required, the District Magistrate, and the Superintendent of Police, and shall also be web enabled so as to be in the public domain simultaneously for the media and citizens to access it.
  - (c) The Head of the institution shall be obliged to act immediately in response to the information received from the Anti-ragging Helpline as at sub-clause of this clause.
  - (d) The telephone numbers of the Anti-ragging Helpline and all the important functionaries in every institution, Heads of institutions, faculty members, members of the anti-ragging committees and anti-ragging squads, district and sub-divisional authorities and state authorities, Wardens of hostels, and other functionaries or authorities where relevant, shall be widely disseminated for access or to seek help in emergencies.
  - (e) The All India Council for Technical Education, the Central Government or the agency authorized for the purpose shall maintain an appropriate database to be created out of affidavits, affirmed by each student and his/her parents/guardians and stored electronically by the institution; and such

database shall also function as a record of ragging complaints received, and the status of the action taken thereon.

- (g) The All India Council for Technical Education, the Central Government or the agency authorized for the purpose shall make available the database to a non-governmental agency to be nominated by the Central Government, to build confidence in the public and also to provide information of non-compliance with these Regulations to the Councils and to such bodies as may be authorized by the All India Council for Technical Education/Central Government.

**11. The All India Council for Technical Education shall take the following regulatory steps, namely :—**

- (a) The All India Council for Technical Education shall make it mandatory for the institutions to incorporate in their prospectus, the directions of the Central Government or the State Level Monitoring Committee with regard to prohibition and consequences of ragging, and that non-compliance with these Regulations and directions so provided, shall be considered as lowering of academic standards by the institution, therefore making it liable for appropriate action.
- (b) The All India Council for Technical Education shall verify that the institutions strictly comply with the requirement of getting the affidavits from the students and their parents/guardians as envisaged under these Regulations.
- (c) The All India Council for Technical Education shall include a specific condition in the Utilization Certificate, in respect of any financial assistance or grants-in-aid to any institution under any of the general or special schemes of

the All India Council for Technical Education, that the institution has complied with the anti-ragging measures.

- (d) Any incident of ragging in an institution shall adversely affect its accreditation, ranking or grading by National Board of Accreditation or by any other authorised accreditation agencies while assessing the institution for accreditation, ranking or grading purposes.
- (e) The All India Council for Technical Education shall constitute an Inter-Council Committee, consisting of representatives of the various Councils, the Non-Governmental agency responsible for monitoring the database maintained by the All India Council for Technical Education/Central Government and such other bodies in higher education, to coordinate and monitor the anti-ragging measures in institutions across the country and to make recommendations from time to time; and shall meet at least once in six months each year.
- (f) The All India Council for Technical Education shall institute an Anti-Ragging Cell within the AICTE as an institutional mechanism to provide secretarial support for collection of information and monitoring, and to coordinate with the State Level Monitoring Cells and University Level Committees for effective implementation of anti-ragging measures, and the Cell shall also coordinate with the Non-Governmental agency responsible for monitoring the database maintained by the All India Council for Technical Education/Central Government.

[ADVT III/4/162/2009/Ext.]

Dr. K. NARAYANA RAO, Member Secy.